

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 75/2018

बउनवान

विनोद आयु 23 साल पुत्र श्री रणजीत, जाति मीणा, निवासी बालून्दा, तहसील मांगरोल,  
जिला बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज०) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)  
(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 28.09.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 16.02.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बालून्दा तहसील-मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1.60 है., किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 2560 /- रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है। पत्रावली में बेदखलीनामा एवं पैमाइश रिपोर्ट संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र

जिला कलेक्टर  
बारां (राज०)

हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेटोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 02/2017 निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 211, रकबा 1.60 है। किस्म-चारागाह ग्राम बालून्दा पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 02/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2017 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से तथा अपीलांत द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति रसीद संख्या 36/034351 एवं 21/034352 से भी प्रमाणित है। छायाप्रतियां रसीदात से स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा पांच फसलों का आरोपित जुर्माना एवं फसल नीलामी सजायाब होने के पश्चात अदा किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोलं द्वारा प्रकरण संख्या 09/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर  
बारा (राज.)